

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक २० सितम्बर, 2013.

विषय:- जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल में केन्द्रीय विद्यालय के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु ०.९५ हेतु ०.९५ हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन को प्रत्यावर्तन।

गहोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: ५७९/१जी-२२७७ (नैनी०) दिनांक ३०-०८-२०१३ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल में केन्द्रीय विद्यालय के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु ०.९५ हेतु ०.९५ हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-८बी/यू.सी.पी./०९/३८०/२००८/एफ.सी./५१ दिनांक २७-०८-२०१३ में दी गई स्वीकृति के आधार पर, निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं :—

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा १०० वृक्षों का वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वर्तों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।

11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से निर्माण में भिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गई योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी०, 100 वृक्षों के वृक्षारोपण, एवं प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव से सम्बन्धित सभी ग्राम सभाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, जिसमें स्पष्ट अंकित हो कि ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार के सभी दावों का निस्तारण हो चुका है एवं ग्राम सभा वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर सहमत है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। उक्त सूचना यथाशीघ्र भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कैम्प कार्यालय, देहरादून एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं०-१०४/२६/प्र०स०-आ०व०ग्रा०वी० दि०-१-१-२००१, कार्यालय ज्ञाप सं०-११०/२६/प्र०स०-आ०व०ग्रा०वी० दि०-४-१-२००१ एवं प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-२, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या २८/१८(२)/२००९ दिनांक ०६-०१-२००९ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

मरदीय,

(राजेन्द्र कुमार)  
अपर सचिव।

संख्या:-जी०आई०: २७८७/७-१-२०१३-८००(२९०२)/२००८ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैकटर-एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, जनपद-नैनीताल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
7. प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, भीमताल, नैनीताल।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, (NIC) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन.आई.सी. की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)  
अपर सचिव।